सीबीआई चीफ वर्मा राफेल मामले में ले सकते थे प्राथमिक जांच कराने का फैसला

स्वाति चतुर्वेदी

सीबीआई चीफ आलोक वर्मा की अपने पद पर बहाली पीएम नरेंद्र मोदी, वित्तमंत्री अरुण जेटली और आधी रात को वर्मा के तख्तापलट के फैसले को लागू करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल, के चेहरे पर अंडा फटने जैसा है।

वर्मा के नजदीकी सूत्रों ने बताया था कि आधी रात के तख्ता पलट के पीछे वर्मा द्वारा राफेल मामले में प्राथमिक जांच के फैसले की आशंका थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच नहीं हो जाती है वो कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकते हैं। मोदी सरकार के स्पिन मास्टर और पन्ना प्रमुख तत्काल मामले की स्पिन में जुट गए और उन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि वर्मा केवल एक लंगड़े निदेशक हैं। जो कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते हैं। दरअसल उनको राफेल मामले में जांच का डर सता रहा है। आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि भ्रष्टाचार के किसी आपराधिक मामले में प्राथमिक जांच की शुरुआत करना किसी नीतिगत फैसले में नहीं आता है। बल्कि ये सीबीआई निदेशक के अधिकार क्षेत्र में है।

ऐसा माना जा रहा है कि मोदी सरकार के गले पर पड़े इस तगड़े तमाचे के बाद वर्मा कुर्सी संभालते ही जो पहला काम करेंगे वो राफेल मामले में प्राथमिक जांच का फैसला होगा। आधिकारिक सूत्रों ने इन पंक्तियों के लेखक को बताया कि मोदी सरकार वर्मा के पास लगातार इस तरह के संकेत भेज रही थी कि 2 फरवरी को रिटायर होने के बाद उन्हें किसी राज्य का गवर्नर नियुक्त कर दिया जाएगा। इसके पीछे उद्देश्य ये था कि वर्मा राफेल मामले में ऐसा कुछ न करें जिससे मोदी को किसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़े।

बड़े अफसर सत्ता से जुड़े लोगों की इस स्पिन पर हंस रहे हैं कि वर्मा कोई जांच के आदेश नहीं दे सकते हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा क्या आप मजाक कर रही हैं? वैध तरीके से नियुक्त किया गया सीबीआई निदेशक प्राथमिक जांच का एक आदेश नहीं दे सकता है जबकि मोदी सरकार द्वारा अवैध रूप से बैठाए गए निदेशक राव मोदी सरकार की बदले की कार्रवाइयों के तहत अखिलेश यादव के खिलाफ

ढेर सारी प्राथमिक जांचों के आदेश दे सकते हैं?

गौरतलब है कि मोदी के लठैत के तौर पर डोवाल के अक्तूबर की रात में दो बजे तख्ता पलट को अंजाम देने के बाद वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया था। मोदी के एक वरिष्ठ मंत्री ने अपना नाम न देने की शर्त पर कहा कि अब ये मोदी जी के लिए बेहतर होगा कि वो डोवाल से इस्तीफा ले लें क्योंकि उन्हें जो भी काम दिया गया उसका उन्होंने कबाड़ा निकाल दिया। शायद उनकी उम्र 70 प्लस हो गयी है जो अब उनके खिलाफ जाती है।

इस तख्ता पलट के दूसरे किरदार जिन्हें ब्लाग मंत्री के तौर पर भी जाना जाता है- जेटली ने वकील के अपने अवतार में मोदी को सलाह दी थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा और न ही वर्मा को फिर से बहाल करेगा। इस फैसले को जायज ठहराने के लिए जेटली ने ढेर सारी प्रेस कांफ्रेंस की थी साथ ही उन्होंने इस पर कई ब्लाग लिख डाले थे।

वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि जेटली ने बिल्कुल साफ-साफ कानून से जुड़े एक ऐस मसले में मोदी को गुमराह करने का काम किया जिसमें उनका अनुभव है। जेटली मोदी के भीतर समाये सीबीआई जांच के डर का अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद मोदी को डोवाल और जेटली जैसे अपने इन भरोसेमंद लोगों के बारे में फिर से विचार करने की जरूरत है।

मैं वर्मा को पिछले 20 साल से जानती हूं। वो हमेशा एक बिल्कुल सीधी रेखा वाले अधिकारी रहे हैं जो कानून का अक्षरशः पालन करने में विश्वास करता है। वर्मा मोदी के पीएमओ द्वारा अवैध मांगों से बेहद परेशानी महसूस कर रहे थे। इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह द्वारा अपने विरोधियों के खिलाफ बदले की कार्रवाई की अपेक्षा से वो बिल्कुल अंदर से व्यथित थे। उसके बाद मोदी की मनमानी को पूरा करने के लिए गुजरात कैडर के दूसरे अफसर राकेश अस्थाना को स्पेशल डायरेक्टर बना कर ले आया गया। बताया जाता है कि जब वर्मा को हटाया गया उस समय वो राफेल मामले में न केवल प्राथमिक जांच की घोषणा करने वाले थे बल्कि कथित भ्रष्टाचार के मामले में अस्थाना की गिरफ्तारी का भी उन्होंने फैसला ले लिया था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये तमाचा उस समय लगा है जब मोदी सरकार उन सभी संस्थाओं पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमले कर रही है जो चेक एंड बैलेंस के जरिये लोकतंत्र को संचालित करने का काम करते हैं। स्वतंत्र तौर पर काम करने वाले अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बड़ी सौगात लेकर आया है। यहां ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि ये फैसला उस समय आया है जब मोदी सरकार उच्च जातियों के अवैध आरक्षण को लागू करने के जरिये एक बार फिर नरेटिव को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है।

यूपी में बीजेपी की खेती चरने को तैयार योगी के साँड़ !

शेषनारायण सिंह

छुट्टा सांड उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में बहुत नुक्सान कर रहे हैं. सरकार की पशुओं के प्रति नीति इस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार है . जहां 2014 में मोदी लहर थी ,वहां आज इस एक कारण से केंद्र और राज्य सरकार की निंदा हो रही है . दिल्ली में बैठे जो ज्ञाता जातियों के आधार पर हिसाब किताब लगाकर उत्तर प्रदेश के 2019 के नतीजों का आकलन कर रहे हैं ,उनको कुछ नहीं मालूम।

अजीब बात यह है कि 325 विधायक और 70 के करीब लोकसभा के सदस्य अपने नेताओं को बता नहीं पा रहे हैं कि उनकी पार्टी की हालत इन आवारा पशुओं के कारण कितनी खराब है . मेरे अपने क्षेत्र में हज़ारों की संख्या में ऐसे जानवर घूम रहे हैं जो किसी के नहीं हैं , झुण्ड के झुण्ड के आ जाते हैं और बस कुछ मिनट में फसलों को बेकार करके चले जाते हैं .

कल खबर आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े तामझाम से मेरे क्षेत्र के गजापुर गाँव में 52 बीघे ज़मीन में सरकारी गौशाला बनवाने का काम शुरू किया है . इस गौशाला में कितने जानवर बंद किये जा सकेंगें यह लखनऊ में बैठे अफसरों को नहीं मालूम है. अगर उनको यह उम्मीद है कि इसके बाद आवारा जानवरों की समस्या खत्म हो जायेगी तो वे सच्चाई को शुतुरमुर्गी स्टाइल में समझ रहे हैं . इस खबर में यह भी बताया गया है कि जो लोग अपने जानवर छुट्टा छोड़ रहे हैं उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी यानी बीजेपी के कुछ वोटर और नाराज़ किये जायेंगें और उनको पुलिस के वसूली तंत्र का शिकार बनाया जाएगा .

मेरे लिए अभी यह अंदाज़ा लगा पाना असंभव है कि 2019 में बीजेपी का कितना नुकसान होगा लेकिन यह तय है कि बड़ी संख्या में किसान बीजेपी के खिलाफ वोट कर सकते हैं और उनकी जाति कुछ भी हो सकती है . 2014 में बीजेपी के कट्टर समर्थकों से भी बात करके यही समझ में आता है कि नाराज़गी बहुत ज्यादा है . अभी करीब सौ दिन बाकी हैं मतदान शुरू होने में. क्या इतने दिनों में ऐसा कुछ कर पायेंगे कि वोटों में होने वाले निश्चित नुक्सान को कम किया जा सके ?

रमा शंकर सिंह ?

किसी को अच्छा या बुरा लगता रहे, भावनायें आहत होतीं रहे पर यह चाहे आज मान लें या कल कि अगले पाँच दस सालों में गाँवों के वे लोग जो पशुपालक रहे हैं ,सदैव से हैं ,वे संगठित होकर लाठी बल्लम लेकर गोगुंडों का मुक़ाबला करते हुये ट्रकों में भरकर खुद अपने या सबके अनुपत्पादक पशुधन को खुद ले जाकर वहाँ छोड़ देंगे या बेच देंगे जहाँ वैज्ञानिक रीति से उन्हें डिब्बा बंद कर निर्यात कर दिया जायेगा।

अभी वे लोग जो गाँवों की डूबती अर्थव्यवस्था से कतई अनभिज्ञ रहे हैं वे एक्सपर्ट बनकर गोनीति बनाते रहे हैं। बाबा, महंत , संत, शंकराचार्य टाइप लोग कुछ मेहनत कर कमाते तो हैं नहीं, बस दूसरों के पैसे से बकबास करना जानते हैं। आज यूपी के गाँवों में जायें और गोरक्षा की बात करके देखें। किसान सबसे पहले अपनी फ़सल को बचायेगा जो नज़र हटते ही आवारा पशु नष्ट कर रहे हैं। ज्यादा हिंदुत्व बघारेंगें तो वह भी नहीं बचेगा जो अभी हाथ में है। गॉव के कारण ही तुम्हारा धर्म अभी तक बचा है। वही हाथ से निकाल दोगे तो ठनठन गोपाल रह जाओगे, जो देश के लिये तो अच्छा ही होगा पर ऐसी ऐतिहासिक चीज़ होगी कि प्रचारकों से ही मूल चीज़ नष्ट हुई। योगी जैसे क्रिमिनल और धर्मांध जीवन भर चढ़ावे पर मौज करते रहे हैं, उनके लिये गाय एक राजनीतिक धार्मिक पशु है, वोट कबाड़ने का आसान ज़रिया, पर बहुत दिनों तक यह रहने वाला नहीं है । अब नौबत यह आ गई कि गो का मुद्दा ही राजनीतिक नहीं रह जायेगा।

दूसरा, मैं पहले ही कह चुका हूँ यदि किसी भी कारण से मंदिर के सवाल पर भी भाजपा चुनाव नहीं जीत सकी तो सदैव के लिये न सिर्फ मंदिर का सवाल बल्कि आपके इस मुद्दे की अपराजेयता पर भी प्रश्नचिन्ह लग जायेगा! क्या ये इसके लिये तैयार है ? ज़ाहिर है कि ऐसा ही है, इन्हें सिर्फ चुनाव से मतलब है। हिंदुओं का सबसे बडा दुश्मन आज हिंदुत्व ही बन गया है।

गांधी को याद करें। गोरक्षा नहीं गोसेवा के पक्षधर थे गांधी। आज भूखे गो परिवार को किन तत्वों ने आवारा भटकने को मजबूर कर दिया है ?

भड़केगा आरक्षण आंदोलन: महाराष्ट्र में पिछड़ों ने की आरक्षण बढ़ाने की मांग, 25 फरवरी को रैली

चरण सिंह राजपूत

जमीनी मुद्दों से ध्यान बांटने में माहिर भाजपा ने लोकसभा चुनाव के ठीक पहले लोगों को आरक्षण के झांसे में उलझा दिया है। जो लोग बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिकता जैसे मुद्दों को लेकर मोदी सरकार को घेर रहे थे उनका दिमाग अब आरक्षण पर आकर अटक गया है। आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण देने के मोदी सरकार की कवायद का जवाब देने के लिए महाराष्ट्र ओबीसी संघर्ष समन्वय समिति खड़ी हो गई है। समिति ने 25 फरवरी को महाराष्ट्र में रैली करने का ऐलान कर दिया है। समिति के अध्यक्ष ने अपनी आबादी 52 फीसद बताते हुए आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग की है।

ओबीसी नेता प्रकाश अन्ना सेगड़े को आंदोलन के नेतृत्व की जिम्मेदारी दी गई। समिति के इस कदम के साथ दूसरे कई संगठन भी बताये जा रहे हैं। समिति के नेता पिछड़े वर्ग के नेताओं को साधने में लग गए हैं। समिति के नेता कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के भी ओबीसी नेताओं से मिलने की रणनीति बना रहे हैं। आंदोलन को धार देने के लिए एससी/एसटी नेताओं के समर्थन के भी प्रयास किये जा रहे हैं।

महाराष्ट्र में ओबीसी का 27 प्रतिशत आरक्षण है। यह आरक्षण शिक्षण संस्थानों के साथ ही सरकारी नौकरियों में भी लागू होता है। स्थानीय चुनाव में भी ये लोग इस आरक्षण का फायदा उठाते हैं।सवर्णों में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10 फीसदी आरक्षण देने का 124वां संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में भी पास होने के बाद पिछड़े व दलित संगठन सचेत हो गए हैं।

ज्ञात हो कि बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव इस आरक्षण का विरोध कर पहले ही पिछड़ों के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण का विरोध शुरू हो चुका है। कल लखनऊ में इसके विरोध में धरना दिया गया। राजनीतिक दलों में भी राजद के अलावा ओवैसी और डीएमके ने भी इसका विरोध किया है।

कांग्रेस, सपा, बसपा, जदयू और लोजपा ने इसका विरोध न किया हो पर इन संगठनों के पिछड़े वर्ग के नेताओं का समिति से संवाद शुरू हो चुका है। भले ही दलित नेता रामविलास पासवान इस मामले पर मोदी सरकार की पैरवी कर रहे हों। ऐसा न करने पर आरक्षण खत्म होने की बात कर रहे हों पर सरकार के इस कदम को आरक्षण खत्म करने की कवायद मानकर आंदोलन शुरू हो चुके हैं। सामान्य वर्ग के गरीब लोग भी 8 लाख तक आय का विरोध करने लगे हैं। उनको आशंका है कि इससे उनकी हक मारी जाएगी।

मोदी सरकार के सवर्णों को 10 फीसद आरक्षण देने इस हथकंडे के बाद अब देश में फिर से आरक्षण आंदोलन के भड़कने की आशंका हो गई है। जिस तरह 1989 में वीपी सिंह के मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद सवर्ण छात्रों का आंदोलन भड़का था उसी तरह से अब पिछड़े वर्ग ने आंदोलन करने के लिए कमर कस ली है।

केरल में स्तन ढकने के लिए महिलाओं ने किया था विद्रोह

अशोक बैरवा 'मूल निवासी'

जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थीं और निचली जातियों की महिलाओं को उनके स्तन न ढकने का आदेश था। उल्लंघन करने पर उन्हें 'ब्रेस्ट टैक्स' यानी 'स्तन कर' देना पड़ता था।

नंगेली का नाम केरल के बाहर शायद किसी ने न सुना हो। किसी स्कूल के इतिहास की किताब में उनका जिक्र या कोई तस्वीर भी नहीं मिलेगी।

लेकिन उनके साहस की मिसाल ऐसी है कि एक बार जानने पर कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि केरल के चेरथला की नंगेली ने स्तन ढकने के अधिकार के लिए अपने ही स्तन काट दिए थे।

केरल के इतिहास के पन्नों में छिपी ये लगभग सौ से डेढ़ सौ साल पुरानी कहानी उस समय की है, जब केरल के बड़े भाग में ब्राह्मण त्रावणकोर के राजा का शासन था।

जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थीं और निचली जातियों की महिलाओं को उनके स्तन न ढकने का आदेश था। उल्लंघन करने पर उन्हें 'ब्रेस्ट टैक्स' यानी 'स्तन कर' देना पड़ता था।

केरल के श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में जेंडर इकॉलॉजी और दलित स्टडीज़ की एसोसिएट प्रोफ़ेसर डॉ. शीबा केएम बताती हैं कि ये वो समय था जब पहनावे के कायदे ऐसे थे कि एक व्यक्ति को देखते ही उसकी जाति की पहचान की जा सकती थी।

डॉ. शीबा कहती हैं, ब्रेस्ट टैक्स का मक़सद जातिवाद के ढांचे को बनाए रखना था। ये एक तरह से एक औरत के निचली जाति से होने की कीमत थी। इस कर को बार-बार अदा कर पाना इन ग़रीब समुदायों के लिए मुमकिन नहीं था।

केरल के हिंदुओं में जाति के ढांचे में नायर जाति को शूद्र माना जाता था जिनसे निचले स्तर पर एड़वा और फिर दलित समुदायों को रखा जाता था।

कर मांगने आए अधिकारी ने जब नंगेली की बात को नहीं माना तो नंगेली ने अपने स्तन खुद काटकर उसके सामने रख दिए।

लेकिन इस साहस के बाद खून ज़्यादा बहने से नंगेली की मौत हो गई। बताया जाता है कि नंगेली के दाह संस्कार के दौरान उनके पति ने भी अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी।

आखिर एक लम्बे संघर्ष के उपरांत त्रावणकोर के राजा को घोषणा करनी पड़ी कि सभी महिलाएं शरीर का ऊपरी हिस्सा वस्त्र से ढक सकती हैं। 26 जुलाई 1859 को राजा के एक आदेश के जरिए महिलाओं के ऊपरी वस्त्र न पहनने के कानून को बदल दिया गया।

नंगेली की याद में उस जगह का नाम मुलच्छीपुरम यानी 'स्तन का स्थान' रख दिया गया, पर समय के साथ अब वहां से नंगेली का परिवार चला गया है और साथ ही इलाके का नाम भी बदलकर मनोरमा जंक्शन पड़ गया है।

उन्होंने (नंगेली ने) अपने लिए नहीं बल्कि सारी औरतों के लिए ये कदम उठाया था। नंगेली आपकी अमर गाथा लिखी जाएगी सुनहरे अक्षरों में मनुवाद और ब्राह्मणवाद का यह ऐसा कर्कश दृश्य था कि एक औरत को उसकी जाति के आधार पर उसके स्तन तक को न ढकने दिया हो। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।